Diversion of Central fun* by States

2603 DR. D. VENKATESHWAR Ra0: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Planning Com-gajga has waried the Chief Minister that their annual allocations would be drastically out if 'hey were found misusing the funds given for completing Centrally funded projects in their States;

(b) if so, whether the Planning Commission had noticed i_n the past that many State Governments had diverted their funds from Centrally-funded projects; and

(c) if so, the names of the States held responsible in this regard and the action proposed to be taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHAHESHWAR SAVANOOR): (a) to (c) The Normal Plan Assistance y Central Government for State Pl*ns U formula based and is given » the form of Block Loans/Gran ta •nd is not linked to any specific pro->«« Only Special Category States are permitted to use upto 20 percent of normal plan assstance for meeting nemral•J plan assistance for meeting /"^ "oo-plan gap Special central assitace is also being provid-od to the state bsaic minimum tfeta *(BUS)* and Area Develop- Programmes but these a'«ao rally not linked to any parti N project Central assistance "a provided lor Accelerated Programme which la project baaed and | to saetehmg share by State Implementation laetadtag sanctioning the to beor carrtexd out by release of funds

Ceneral Assistance is also provided for Central Sponsored Scheme! (CSS) which is linked to State's contribution unless it is 100% Centrally Sponsored Scheme and is released by various Central Ministrtes/Depart-ments depending on their implementation. The expenditure on these projcctsischemes are monitored by the concerned ministries and not by the Planning Commission.

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान करना

2604. **श्री गोविन्दराम सिरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन राज्यों को, जहां संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में योजना के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई तथा जिस्तरीय जिला पंचायतों एवं नगरीय निकायों का गठन किया जा चुका है और ऐसी संस्थाओं ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु विकास कार्य के लिए गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के आधार पर केन्द्रीय सहायता देने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर) : (क) और (ख) जी, नहीं; प्रश्न नहीं उठता ।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत दरभंगा में कार्यान्वित की गई परियोजनाएं

2605. **श्री रामगोपाल यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के स्थापना वर्ष से लेकर 31 मार्च, 1997 तक दरभंगा (बिहार) के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा इस योजना के अन्तर्गत दरभंगा में कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ख) अब तक कितनी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सबनूर) : (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत 1993-94 से 1996-97 के वर्षों के लिए दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सदस्य श्री अशरफ फातमी के लिए 305 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 168.68 लाख रुपये खर्च किए जा चुके है एवं 313 योजनाएं पूरी की जा चुकी है ।

शहरी क्षेत्रों में निर्धन तथा धनी लोगों का मूल्यांकन

2606. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा अत्यधिक धनी लोगों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों वर्गों के लोगों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) प्रत्येक वर्ग की वार्षिक आय का अनुमानित औसत क्या है ; और

(घ) यदि सरकार द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सबनूर) : (क) नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 1993-94 में, प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति के 281.35 रुपये के उपभोग व्यय के अर्थ में, 32.36 प्रतिशत शहरी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी । अत्यधिक धनी लोगों की कोई मानक परिभाषा नहीं है । हालांकि 1993-94 के उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 4.9 प्रतिशत लोगों को 1955 रुपये से अधिक प्रतिमाह के प्रतिमाह प्रति व्यक्ति व्यय के उच्च व्यय कोष्ठक में वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) 1993-94 में शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या के 76.34 मिलियन होने का अनुमान है । शहरी क्षेत्रों में ही 1955 रुपये से अधिक के प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय करने वाले लोगों की संख्या 11.56 मिलियन है ।

(ग) और (घ) प्रश्न पर जानकारी उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1993-94 में शहरी क्षेत्रों में, लगभग 62.74 प्रतिशत जनसंख्या का प्रति व्यक्ति उपभोग 492 रुपये प्रतिमाह था ।

विकास हेतु पहचाने गए प्राथमिकता क्षेत्र

2607. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के प्रयोजनार्थ प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है ;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से है ; और

(ग) इन प्राथमिक क्षेत्रों का किन कम में अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सबनूर) : (क) और (ख) जी, हां । पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने और गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाती है । सुरक्षित पेयजल, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, आवास और सर्वव्यापी सम्पर्क की बुनियादी न्यूनतम सेवाएं भी नौवीं योजना हेतु ध्यान के महत्वपूर्ण क्षेत्र है ।